



INTERNATIONAL JOURNAL OF TRENDS IN EMERGING RESEARCH AND DEVELOPMENT

INTERNATIONAL JOURNAL OF TRENDS IN EMERGING RESEARCH AND DEVELOPMENT

Volume 3; Issue 4; 2025; Page No. 313-317

Received: 10-05-2025
Accepted: 16-06-2025
Published: 17-07-2025

अंबेडकर नगर जिले (उत्तर प्रदेश) में प्रजनन क्षमता और परिवार कल्याण कार्यक्रमों का अध्ययन और जनसंख्या वितरण

¹Ajay Kumar and ²Dr. Ram Bachan Maurya

¹Research Scholar, Mahakaushal University, Jabalpur, Madhya Pradesh, India

²Professor, Mahakaushal University, Jabalpur, Madhya Pradesh, India

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20106758>

Corresponding Author: Ajay Kumar

सारांश

उत्तर प्रदेश, भारत का सबसे अधिक आबादी वाला और चौथा सबसे बड़ा राज्य है। यह देश के उत्तर-मध्य भाग में स्थित है। उत्तर प्रदेश की सीमा उत्तर में उत्तराखंड राज्य और नेपाल देश से, पूर्व में बिहार राज्य से, दक्षिण-पूर्व में झारखंड और छत्तीसगढ़ राज्यों से, दक्षिण में मध्य प्रदेश राज्य से, और पश्चिम में राजस्थान और हरियाणा राज्यों और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली से लगती है। 26 जनवरी, 1950 को, जब भारत एक गणतंत्र बना, तो राज्य को इसका वर्तमान नाम उत्तर प्रदेश (शाब्दिक रूप से, "उत्तरी राज्य") दिया गया। इसकी राजधानी लखनऊ है, जो राज्य के पश्चिम-मध्य भाग में स्थित है।

मूलशब्द: जनसंख्या अध्ययन, अंबेडकर नगर जिला, प्रजनन क्षमता, परिवार नियोजन, सामाजिक-आर्थिक कारक

प्रस्तावना

जब भी कोई देश कठिन परिस्थितियों और चुनौतियों का सामना करता है, चाहे वे राजनीतिक हों या आर्थिक, बुद्धिजीवियों और राजनेताओं को किसी न किसी मोड़ पर अपने देश के इतिहास में समाधान ढूँढ़ने की ज़रूरत पड़ती है। देश को आकार देने वाली ऐतिहासिक घटनाएँ, लोग और उनके विचार, देश की वर्तमान चुनौतियों के समाधान के लिए महत्वपूर्ण तत्व साबित होते हैं। डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर हमारे महानतम न्यायविदों, अर्थशास्त्रियों, मानवाधिकारों के लिए संघर्षरत योद्धा और समाज सुधारकों में से एक थे। भारत में सामाजिक पूर्वाग्रहों के विरुद्ध डॉ. आंबेडकर के संघर्ष के बारे में तो सब जानते हैं, लेकिन यह बात कम ही लोग जानते हैं कि उन्होंने अपने विचारों और चिंतन से अर्थव्यवस्था पर भी कैसा प्रभाव डाला।

एक अर्थशास्त्री के रूप में आंबेडकर की पहचान भले ही आम लोगों की नज़रों से ओझल रही हो, लेकिन इसका कारण संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष और भारतीय समाज के पिछड़े और वंचित वर्गों के नेता के रूप में उनकी प्रसिद्धि थी। अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले एशियाई प्रोफेसर अमर्त्य सेन

ने मई 2007 में सर दोराबजी टाटा स्मारक व्याख्यान श्रृंखला में भाषण देते हुए कहा था, "अंबेडकर अर्थशास्त्र में मेरे पिता हैं। उन्होंने आज जो हासिल किया है, उससे कहीं ज़्यादा के वे हक़दार हैं। हालाँकि, वे अपने देश में एक बेहद विवादास्पद व्यक्ति थे, हालाँकि यह वास्तविकता नहीं थी। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में उनका योगदान अद्भुत है और इसे हमेशा याद रखा जाएगा।"

एक अर्थशास्त्री के रूप में, डॉ. आंबेडकर ने यह प्रतिपादित किया कि राज्य भूमि का स्वामी है। उनके अनुसार, बुनियादी उद्योगों पर राज्य का एकाधिकार होना चाहिए और बाकी पर निजी स्वामियों का नियंत्रण होना चाहिए। उनका मानना था कि "लोकतांत्रिक राज्य समाजवाद" भूमि, कुछ बुनियादी उद्योगों, धर्मों, जाति पर राज्य के नियंत्रण और संवैधानिक पद्धति की एक विस्तृत योजना के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। उनके अनुसार, जातिगत चेतना सभी आर्थिक प्रणालियों में बाधा डालती है।³ आश्चर्यजनक रूप से, डॉ. आंबेडकर ने 1923 में ही राज्य के स्वामित्व वाले बुनियादी उद्योगों, भूमि और बीमा के साथ-साथ मुक्त अर्थव्यवस्था, वैश्वीकरण, उदारीकरण और निजीकरण का भी सुझाव दिया था। उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया था कि यदि मुक्त अर्थव्यवस्था की

नीति को सफल बनाना है तो रुपये का मूल्य स्थिर रखना होगा। इसलिए, यह कहा जा सकता है कि अमेरिका और ब्रिटेन में शिक्षित डॉ. आंबेडकर "एक आरामकुर्सी अर्थशास्त्री नहीं" थे, बल्कि वे "विचार और कर्म में एक दुर्लभ दृष्टि वाले अर्थशास्त्री" थे।

जनसंख्या गतिशीलता

सांख्यिकीय दृष्टि से, जनसंख्या व्यक्तियों का एक समूह है जो समान मानदंडों द्वारा परिभाषित होते हैं, लेकिन विभिन्न विशेषताओं के लिए विभिन्न मान रखते हैं। जनसंख्या को हमेशा ऐसे व्यक्तियों के समूहों के रूप में भी माना जा सकता है जिनके दिए गए गुणों के लिए समान मान होते हैं। इसलिए, जनसंख्या की मुख्य विशेषता उसका आकार (उसे बनाने वाले व्यक्तियों की संख्या) और उसकी संरचना (विशेषताओं से जुड़े विभिन्न मानों की आवृत्तियाँ) है। पहली नज़र में, यह स्पष्ट रूप से मानव आबादी पर लागू होता है, जो जनसांख्यिकी का विषय है। हालाँकि, मानव आबादी समय में स्थिर नहीं है, बल्कि निरंतर परिवर्तन की स्थिति में है। जनसांख्यिकी विश्लेषण मुख्य रूप से उस परिवर्तन के अंतर्निहित तंत्रों का अध्ययन करता है (अर्थात्, जनसंख्या गतिशीलता को समझने के लिए)।

किसी जनसंख्या की गतिशीलता की पहली विशेषता उसकी एक निश्चित दर से बढ़ने या घटने की क्षमता है। इसी कारण से, इस खंड का पहला भाग जनसंख्या वृद्धि पर विचार करता है। अध्याय 1 जनसांख्यिकीविदों द्वारा जनसंख्या और व्यक्तियों से क्या तात्पर्य है, इस पर अधिक विस्तार से विचार करता है; जबकि अध्याय 3 इस बात की जाँच करता है कि जनसंख्या वृद्धि उसके प्राकृतिक (जन्म और मृत्यु) और प्रवासी घटकों पर कैसे निर्भर करती है। ये तीन संक्षिप्त परिचयात्मक अध्याय अध्याय 4 में विश्लेषित एक समस्या की ओर ले जाते हैं: यह तथ्य कि वृद्धि के तंत्र को जनसंख्या की आयु और लिंग संरचना से स्वतंत्र रूप से नहीं समझा जा सकता है। जनसंख्या की गति और संरचना अविभाज्य हैं: न केवल प्रजनन क्षमता, मृत्यु दर या प्रवासन पैटर्न में बदलाव के कारण जनसंख्या संरचना लगातार बदलती रहती है, बल्कि संरचनात्मक परिवर्तन स्वयं भी इस बात को प्रभावित करते हैं कि परिवर्तन के ये कारक जनसंख्या वृद्धि दर में कैसे परिलक्षित होते हैं।

साहित्य की समीक्षा

अभय एट अल (2015) ^[1] जनसंख्या और विकास अनुसंधान के लिए एक जटिल क्षेत्र है और इसमें कई चर से संबंधित मुद्दे शामिल हैं, जैसे जनसांख्यिकी, अर्थशास्त्र, शहरीकरण, लिंग, धर्म, राजनीति, भोजन और पोषण, स्वास्थ्य, मानवाधिकार आदि। भारतीय जनगणना का उपयोग घरेलू स्तर पर व्यापक डेटा एकत्र करने के लिए किया जाता है। आय के स्रोत के बारे में व्यापक जानकारी, जनसांख्यिकीय चर पर जानकारी, घरेलू सामान, विभिन्न टिकाऊ घरेलू सामानों का कब्जा आदि जनगणना 2011 में एकत्र की गई है। वर्तमान अध्ययन भारत में अत्यधिक आबादी वाले राज्य उत्तर प्रदेश (यूपी) में जनसंख्या और विकास का विश्लेषण करने का एक प्रयास है। यह पत्र कुछ चुनिंदा सामाजिक-जनसांख्यिकीय चर के संबंध में यूपी के सभी जिलों की स्थिति प्रदान करेगा। इस अध्ययन का निष्कर्ष है कि यूपी के कुछ जिले देश के कई राज्यों की तुलना में बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं

पूजा एट अल (2021) ^[2] महाराष्ट्र नाम मराठी भाषी लोगों की भूमि माना जाता है, और यह संस्कृत के दो शब्दों 'महा' अर्थात् 'महान' और 'राष्ट्र' अर्थात् 'राष्ट्र' से मिलकर बना प्रतीत होता है। इस प्रकार

महाराष्ट्र नाम का स्पष्ट अर्थ है महान राष्ट्र। महाराष्ट्र के एक उत्कृष्ट व्यक्तित्व डॉ. बी.आर. आंबेडकर थे। उन्होंने स्वयं को एक विलक्षण प्रतिभा सिद्ध किया और एक महान क्रांतिकारी, दार्शनिक, सिद्धांतकार, उत्कृष्ट विधिवेत्ता, सामाजिक कार्यकर्ता, रचनात्मक लेखक और आलोचक के रूप में जाने गए। हालाँकि, उनके विचारों को भारतीय समाज की सामान्य धारणा में कभी भी संतोषजनक स्थान नहीं मिला, केवल इसलिए कि वे एक अछूत के रूप में पैदा हुए थे। उनके जीवन का मुख्य उद्देश्य स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के समकालीन लोकतांत्रिक विचारों के अनुरूप समाज का पुनर्निर्माण करना था। उन्होंने हिंदुओं और भारतीय समाज के अन्य वर्गों के लिए समान नागरिक संहिता को संहिताबद्ध करने हेतु सुदृढ़ आधार तैयार करने के लिए सच्चे प्रयास किए थे। उनका दृढ़ विश्वास था कि महिला सशक्तिकरण महिलाओं की सुरक्षा और खुशी से ही संभव है। विश्व स्तर पर महिलाओं के सशक्तिकरण की उपलब्धियों को डॉ. बी.आर. आंबेडकर के विचारों का अनुसरण करना चाहिए। उन्होंने देवदासी प्रथा, बाल विवाह जैसी अनुचित और कुप्रथाओं के विरुद्ध संघर्ष किया और परिवार नियोजन को पुरजोर तरीके से बढ़ावा दिया।

कन्हैया एट अल (2022) ^[3] यह निबंध उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में किए गए एक अनुभवजन्य अध्ययन पर आधारित है। यह दलितों के बीच स्वास्थ्य संसाधनों तक उनकी पहुँच के संबंध में उपजाति स्तर के विश्लेषण की आवश्यकता पर ज़ोर देता है। मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों आँकड़ों का उपयोग करते हुए, अनुसूचित जातियों के भीतर विभिन्न उपजातियों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में असमानताओं पर चर्चा की गई है। स्वास्थ्य, बीमारी और रोग के बारे में धारणाएँ विभिन्न स्वास्थ्य स्थितियों की व्यापकता के बारे में प्रासंगिक जानकारी प्रदान करती हैं, जबकि संकेन्द्रण वक्र दलितों के भीतर विभिन्न उपजातियों के बीच जेब से खर्च, भूमि स्वामित्व और आय में असमानताओं को दर्शाते हैं। उत्तरदाताओं की केस रिपोर्ट स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुँचने में बाधाओं के रूप में सामाजिक पहचान, आर्थिक स्थिति और स्वास्थ्य सेवाओं की स्थानिक दुर्गमता के प्रतिच्छेदन को समझने में मदद करती है।

चंद्रशेखर एट अल (2017) ^[4] डॉ. बी.आर. आंबेडकर उच्च संवैधानिक ज्ञान और कानून के ज्ञान वाले वैश्विक व्यक्तित्व थे। उन्होंने समकालीन जीवन के सभी प्रगतिशील संविधानों का अध्ययन किया और भारत के संविधान की रचना की, जो विश्व का मानक संविधान है। जाति, वर्ग, रंग, लिंग, नस्ल, भाषा, भौगोलिक स्थिति के आधार पर कई सामाजिक बुराइयों और भेदभाव को दूर करने की उनकी कोशिशों को उनके भाषणों की श्रृंखला में संबोधित किया गया है और उन्होंने संवैधानिक प्रयासों के माध्यम से उनके लिए समाधान खोजे हैं। सामाजिक परिवर्तन और विकास के लिए उनकी प्रतिबद्धता निरंतर थी और वे समाज के हाशिए पर पड़े वर्गों को न्याय और सम्मान दिलाने के लिए बेचैन थे। गैर-संस्थागत सामाजिक कार्य अभ्यास भारत में बहुत पहले शुरू हुआ था और हाशिए पर पड़े वर्गों के कल्याण के लिए आंबेडकर के कानूनी प्रयासों के बाद इसे गति मिली।

एमडी अरेफुल एट अल (2024) ^[6] भारत में कई दशकों से मैनुअल स्कैवेंजिंग का प्रचलन रहा है। आज़ादी के 76 साल बाद भी भारत में मैनुअल स्कैवेंजिंग एक अभिशाप की तरह है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने इस मैनुअल स्कैवेंजिंग को "राष्ट्र के लिए शर्म" माना था। इस शोध पत्र का मुख्य उद्देश्य अध्ययन क्षेत्र में मैनुअल स्कैवेंजिंग के सामाजिक-आर्थिक स्वरूप, स्वास्थ्य स्थिति

और कार्यों की प्रकृति की जाँच करना, अध्ययन क्षेत्र में मैनुअल स्कैवेंजर्स के सामने आने वाली प्रमुख समस्याओं और चुनौतियों पर प्रकाश डालना और पश्चिम बंगाल के मालदा जिले में मैला ढोने वालों के कार्य स्वरूप और जीवन की गुणवत्ता में बेहतर सुधार के लिए बहुमूल्य सुझाव देना है। पश्चिम बंगाल के मालदा जिले को अध्ययन क्षेत्र के रूप में चुना गया है। अध्ययन से पता चलता है कि अध्ययन क्षेत्र में मैनुअल स्कैवेंजर्स में अपने वैकल्पिक रोजगार, लाभकारी सरकारी योजनाओं, सुरक्षा उपकरणों और रोजगार लाभों के बारे में जागरूकता का अभाव है।

दिलीप एट अल (2025) [7] डॉ. भीमराव रामजी आंबेडकर का जीवन और कार्य, व्यवस्थित सामाजिक बहिष्कार से लेकर भारत के लोकतांत्रिक और संवैधानिक ढाँचे के प्रमुख निर्माता बनने तक की एक ऐतिहासिक यात्रा का प्रतिनिधित्व करते हैं। महार जाति में जन्मे और अस्पृश्यता की दमनकारी वास्तविकताओं के शिकार, जाति-आधारित भेदभाव के आंबेडकर के शुरुआती अनुभवों ने सामाजिक अन्याय के विरुद्ध आजीवन प्रतिरोध को प्रेरित किया। असाधारण शैक्षणिक उपलब्धियों, राजनीतिक सक्रियता और कानूनी सुधारों के माध्यम से, वे समानता, स्वतंत्रता और सामाजिक न्याय के सिद्धांतों के प्रति प्रतिबद्ध एक अग्रणी व्यक्ति के रूप में उभरे। भारतीय संविधान के प्रारूपण में उनका नेतृत्व, दलित अधिकारों के लिए उनकी वकालत और अंततः बौद्ध धर्म अपनाना, सामाजिक मुक्ति और आध्यात्मिक गरिमा के उनके मिशन में महत्वपूर्ण मील के पत्थर साबित हुए। यह समीक्षा लेख बौद्धिक विद्वता से लेकर संवैधानिक दृष्टि और आध्यात्मिक परिवर्तन तक, आंबेडकर के बहुमुखी योगदानों की पड़ताल करता है और उनके द्वारा प्रेरित व्यापक सामाजिक और राजनीतिक आंदोलनों का भी मूल्यांकन करता है।

अनुसंधान पद्धति

सभ्यता के आरंभ से ही जनसंख्या का आकार विकास संबंधी चर्चाओं का केंद्र रहा है। सामाजिक-आर्थिक विकास और सैन्य संदर्भ में जनसंख्या का आकार चिंता का विषय रहा है। प्राचीन विचारकों ने जनसंख्या की संतुलित वृद्धि की बात की थी ताकि जीवन की गुणवत्ता का एक निश्चित स्तर बनाए रखा जा सके। प्लेटो की दो महान कृतियों, द रिपब्लिक (लगभग 370-380 ईसा पूर्व) और द लॉज (लगभग 340 ईसा पूर्व) में एथेंस और स्पार्टा को ध्यान में रखते हुए नगर-राज्य के लिए नागरिकों का आकार 50-40 निर्धारित किया गया है।

नागरिकों की यह संख्या संभवतः कुल जनसंख्या के 10 से 12 गुना के बराबर है जब महिलाओं, बच्चों और दासों को शामिल किया जाता है। आदर्श संख्या एक अन्य महान विचारक अरस्तू के लिए चिंता का विषय थी। उन्होंने कहा है कि एक अच्छे राज्य के लिए न तो कम और न ही बहुत बड़ी संख्या वांछनीय है। इसी तरह से चीनी दार्शनिक कन्फ्यूशियस इष्टतम जनसंख्या आकार की ओर संकेत करते थे जहां उन्होंने कहा कि बहुत कम जनसंख्या कृषि विकास के लिए वांछनीय नहीं है और साथ ही अगर कृषि में तकनीकी ठहराव है तो उच्च जनसंख्या वृद्धि से राजस्व संग्रह कम हो जाएगा। भारतीय राजनीतिक दार्शनिक चाणक्य ने अपने अर्थशास्त्र में उल्लेख किया है कि एक गाँव में जनसंख्या का आदर्श आकार क्षेत्र की कृषि और खनन क्षमता के आधार पर हर 1-2 वर्ग मील क्षेत्र के लिए 100 से 500 कृषक परिवारों के बीच होना चाहिए।

डेटा स्रोत: जब विद्वान जनसंख्या के आकार के निहितार्थ को

लेकर चिंतित थे, तब भी हाल तक दुनिया भर में जनसंख्या गणना नियमित नहीं थी। हालाँकि, दुनिया के अधिकांश हिस्सों में जनगणना शुरू होने से पहले वैश्विक जनसंख्या प्रवृत्ति के कई अनुमान उपलब्ध थे। वर्तमान समय में जनसंख्या प्रवृत्तियों का अध्ययन करने के लिए देशों की जनगणना प्रमुख डेटा स्रोत है। हालाँकि, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या की वर्तमान प्रवृत्ति और भविष्य के अनुमान प्रदान करने के लिए नियमित रूप से वैश्विक जनसंख्या संभावनाएँ प्रकाशित करता है।

अपर्याप्त साक्ष्यों के कारण, अतीत के जनसंख्या अनुमान व्यापक अटकलों पर आधारित हैं। हाल के अतीत के लिए भी विश्व जनसंख्या का विश्वसनीय अनुमान लगाना कठिन है। पहली आधुनिक जनगणना स्वीडन (1749) में हुई थी। बाद में अमेरिका (1790), ग्रेट ब्रिटेन और फ्रांस (1801) और भारत में 1872 में जनगणना कार्य शुरू किए गए और इनमें से अधिकांश अधूरे थे। कई तृतीय विश्व देशों में जनगणना कार्य द्वितीय विश्व युद्ध के बाद शुरू हुए। इसलिए, 1900 से पहले के जनसंख्या अनुमान अत्यधिक खंडित हैं और विद्वानों के अनुमानों का परिणाम हैं।

परिणाम

जनसंख्या का वितरण और घनत्व

सामान्य वितरण: अध्ययन क्षेत्र में जनसंख्या वितरण का स्वरूप कमोबेश एक समान है, क्योंकि यह क्षेत्र मध्य गंगा घाटी के उपजाऊ मैदान का एक भाग है। जिले की कुल जनसंख्या 2249598 व्यक्ति (1991) है, जो स्थानीय कारकों जैसे स्थानीय राहत, बाढ़ की आवृत्ति, पानी की उपलब्धता, उपजाऊ भूमि, कृषि क्षमता, व्यापार और परिवहन सुविधाएँ, औद्योगीकरण और शहरीकरण आदि से जुड़ी कुछ भिन्नताओं को छोड़कर पूरे जिले में समान रूप से वितरित है। चित्र 3.1 जनसंख्या वितरण की कुछ अनूठी विशेषताओं को प्रकट करता है, जैसे शहरी केंद्रों में जनसंख्या का संकेन्द्रण, द्विफसली क्षेत्र, परिवहन और संचार के विकसित साधन, जबकि ताल, धीमी जलधाराओं और बार-बार बाढ़ की घटनाओं वाले क्षेत्रों में आबादी कम है। सड़क के किनारे, जनसंख्या का संकेन्द्रण टुकड़ों में देखा जाता है।

ब्लॉक स्तर पर, बेरुआरबारी अध्ययन क्षेत्र में सबसे घनी आबादी वाला क्षेत्र है जहाँ जिले की 3.85 प्रतिशत आबादी 2.68 प्रतिशत क्षेत्र में फैली हुई है। इसके बाद हनुमान गंज (5.90% आबादी 4.45% क्षेत्र में), बैरिया (5.69% आबादी 4.51% क्षेत्र में), गरवार (5.15% आबादी 4.36% क्षेत्र में) और दुबहर (कुल आबादी का 5.62% 4.83% क्षेत्र में) का स्थान आता है। ये द्वि-फसलीय क्षेत्र हैं जहाँ सिंचाई और परिवहन की सुविधाएँ विकसित हैं। यहाँ चावल और गेहूँ की सघन खेती होती है और ये बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों से दूर स्थित हैं।

तालिका 1: 1901 से 1951 तक अंबेडकर जिले में जनसंख्या वृद्धि का दशकीय परिवर्तन

| साल | जनसंख्या | दशकीय वृद्धि | |
|------|-----------|--------------|--------|
| | | निरपेक्ष | % आयु |
| 1901 | 12,00,822 | | |
| 1911 | 11,65,680 | -35,142 | -2.93 |
| 1921 | 10,61,745 | -1,03,935 | -8.92 |
| 1931 | 11,71,745 | +1,10,000 | +10.36 |
| 1941 | 13,72,641 | +2,00,896 | +17.15 |
| 1951 | 15,43,506 | +1,70,865 | +12.45 |

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि 20वीं सदी की शुरुआत से लेकर 1951 की जनगणना तक, जो कि स्वतंत्रता से पहले की अवधि है, अंबेडकर जिले की जनसंख्या में तीन लाख से अधिक की वृद्धि हुई है। पाँच दशकों की अवधि के जनसांख्यिकीय इतिहास को दो अलग-अलग अवधियों में वर्गीकृत किया जा सकता है, अर्थात् स्थिर जनसंख्या और लगातार बढ़ती जनसंख्या। दो दशकीय अवधियों, अर्थात् 1901 से 1921 को स्थिर जनसंख्या की अवधि के रूप में मान्यता दी गई है। 20वीं सदी के पहले दो दशकों में, अंबेडकर जिले में जनसंख्या की वृद्धि दर क्रमशः 2.93% और 8.92% गिरी। पूर्ण संख्या के संदर्भ में क्रमशः 35,142 और 1,03,935 व्यक्ति कम हुए। विकास दर में यह गिरावट न केवल जिले में, बल्कि हैजा, प्लेग, इन्फ्लूएंजा जैसी महामारियों और महामारी के देशव्यापी विस्तार और प्रथम विश्व युद्ध आदि के कारण भी हो सकती है। इस प्रकार, 1921 का वर्ष एक महत्वपूर्ण विभाजन साबित हुआ क्योंकि इसके बाद जनसंख्या में लगातार वृद्धि के संकेत दिखने लगे। 1921 से 1951 के दौरान जिले की जनसंख्या में वृद्धि का रुझान रहा। 1921 में जिले की जनसंख्या 10.6 लाख थी, जबकि 1951 में इसमें 15.4 लाख की वृद्धि हुई। तीन दशकों के दौरान यह क्रमशः 10.36%, 17.15% और 12.45% बढ़ी। 30 वर्षों के दौरान जिले की जनसंख्या में लगभग 5 लाख की वृद्धि हुई। यह स्पष्ट है कि महामारी और अकाल आदि के कारण होने वाली असामान्य मौतों को नियंत्रित किया गया। असामान्य मृत्यु दर पर बढ़ते नियंत्रण के कारण 1921 और 1951 के दौरान जनसांख्यिकीय परिवर्तन में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। अर्थव्यवस्था का विकास हुआ, विशेषकर कृषि क्षेत्र में। जिले में मृत्यु दर, जो 40 प्रति हजार थी, में उल्लेखनीय कमी आई। इस प्रकार, 1921-1951 के दौरान जिले में जनसंख्या में निरंतर वृद्धि, मृत्यु दर में तीव्र गिरावट का परिणाम थी।

स्वतंत्रता के बाद जनसंख्या वृद्धि

1947 में, भारत एक स्वतंत्र राष्ट्र बना और योजनाबद्ध आर्थिक विकास का निर्णय लिया। इसलिए, योजना आयोग ने पूरी समस्या का बहुत गंभीरता और गहनता से अध्ययन करने का निर्णय लिया। 1954 में, योजना आयोग के स्वास्थ्य कार्यक्रम पर एक पैनल ने जनसंख्या वृद्धि और परिवार नियोजन की समस्याओं पर रिपोर्ट करने के लिए एक समिति नियुक्त की। इस समिति का मुख्य उद्देश्य यह पता लगाना था कि जनसंख्या इतनी तेजी से क्यों बढ़ रही है। 1956 में, केंद्र सरकार द्वारा एक परिवार नियोजन बोर्ड की स्थापना की गई। नमूना सर्वेक्षणों ने जनसंख्या समस्याओं के बारे में एक और महत्वपूर्ण और उपयोगी डेटा प्रदान किया। पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान, भारत सरकार ने सामाजिक विकास और परिवार कल्याण पर बहुत ध्यान दिया। 1951 से, अंबेडकर जिले की जनसंख्या उच्च वृद्धि दर से बढ़ रही है। खाद्य आपूर्ति की स्थिति में सुधार, चिकित्सा सुविधाओं में सुधार, ये सभी मृत्यु दर में और गिरावट के लिए जिम्मेदार हैं। निम्नलिखित तालिका 1951 से 1991 तक जिले में जनसंख्या वृद्धि को दर्शाती है।

तालिका 2: 1951 से 1991 तक अंबेडकर जिले में जनसंख्या वृद्धि का दशकीय परिवर्तन

| साल | जनसंख्या | दशकीय वृद्धि | |
|------|-----------|--------------|---------|
| | | निरपेक्ष | % आयु |
| 1951 | 15,43,506 | 1,70,865 | + 12.45 |
| 1961 | 17,65,275 | 2,21,769 | + 14.37 |
| 1971 | 21,11,829 | 3,46,554 | + 19.63 |
| 1981 | 25,74,925 | 4,63,096 | + 21.93 |
| 1991 | 32,95,982 | 7,21,057 | + 28.00 |

स्रोत: 1. भारत की जनगणना, 1981 उत्तर प्रदेश भाग II ए, सामान्य जनसंख्या सारणी, पृष्ठ 143 2. सांख्यिकीय पत्रिका, जनपद अंबेडकर 2002 3. जनगणना 2001 के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

उपरोक्त तालिका स्पष्ट रूप से दर्शाती है कि जिले की सामान्य जनसंख्या 1951 से लगातार तीव्र गति से वृद्धि दर का अनुभव कर रही है। 1951 से 1991 तक, चालीस वर्षों की अवधि में जिले की जनसंख्या दोगुनी से भी अधिक हो गई है। 1951 से इसमें लगातार वृद्धि हो रही है। 1951-61 के दौरान, औसत दशकीय वृद्धि दर 14.37 प्रतिशत थी, 1961-71 के दौरान यह बढ़कर 19.63 प्रतिशत हो गई; 1971-81 के दौरान यह 21.91 प्रतिशत थी और 1981-91 के दौरान यह 28.00 प्रतिशत हो गई। जनसंख्या वृद्धि का दशकीय परिवर्तन दर्शाया गया है। औसतन, यह 2 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से बढ़ रही है। पिछले 40 वर्षों के दौरान जिले की जनसंख्या में ऐसी अभूतपूर्व वृद्धि का श्रेय जिले के विभिन्न भागों में बड़े पैमाने पर की गई विकासात्मक गतिविधियों को दिया जा सकता है, जैसे खाद्य आपूर्ति की स्थिति में सुधार, चिकित्सा सेवाओं में सुधार, ये सभी मृत्यु दर में और गिरावट लाने के लिए जिम्मेदार हैं।

अनुमानित मृत्यु दर 1951 में 31 प्रति हजार से घटकर 1991 में 17 प्रति हजार हो गई। हालाँकि प्रजनन दर में गिरावट आई है, फिर भी यह अभी भी क्रमिक रूप से जारी है। मृत्यु दर में तीव्र गिरावट के परिणामस्वरूप, प्राकृतिक वृद्धि और भी अधिक हुई है। जिले के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में वृद्धि के स्वरूप में व्यापक असमानता देखी गई है। हालाँकि जिले की सामान्य जनसंख्या 1951 से ही लगातार बढ़ती जनसंख्या वृद्धि दर का अनुभव कर रही है, फिर भी ग्रामीण क्षेत्रों में वृद्धि कम परिमाण की रही है और शहरी क्षेत्रों में इसके विपरीत अधिक परिमाण की रही है।

पिछली अंतर-जनगणना अवधि (1981-1991) के दौरान, जबकि ग्रामीण जनसंख्या में लगभग 25.4 प्रतिशत की वृद्धि हुई, शहरी जनसंख्या में 45.8 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जैसा कि परिशिष्ट 7 में दिखाया गया है। हालाँकि, जिले की बड़ी संख्या में आबादी अभी भी ग्रामीण इलाकों में रहती है, वास्तविक संख्या के संदर्भ में जिले की लगभग दो तिहाई जनसंख्या वृद्धि ग्रामीण क्षेत्र में हुई है। ग्रामीण बेरोजगारी और बेरोजगारी की समस्या गंभीर अनुपात ग्रहण कर रही है। जब तक उद्योगों के विकेन्द्रीकरण और ग्रामीण इलाकों में उद्योगों के प्रसार के माध्यम से ग्रामीण अर्थव्यवस्था में

संरचनात्मक परिवर्तन नहीं लाए जाते हैं। जिले के ग्रामीण क्षेत्र एक गंभीर सामाजिक-आर्थिक गिरावट की ओर बढ़ रहे हैं। दूसरी ओर, शहरी केंद्र, विशेष रूप से अंबेडकरटाउन के बड़े औद्योगिक केंद्र, बड़े पैमाने पर आप्रवासन का अनुभव कर रहे हैं और यही कारण है कि शहरी क्षेत्रों में तेजी से जनसंख्या वृद्धि दर्ज की जा रही है। शहरीकरण की यह उच्च गति गंभीर समस्याओं से जुड़ी है।

इससे अच्छी कृषि भूमि पर अतिक्रमण होता है, शहरी मलिन बस्तियों का उदय होता है, सामाजिक सुविधाओं की अपर्याप्तता होती है और प्रदूषण के माध्यम से पर्यावरण को नुकसान होता है।

निष्कर्ष

जिले में हिंदू बहुसंख्यक हैं और हिंदी भी बहुसंख्यक लोगों द्वारा बोली जाती है। चिकित्सा सुविधाएँ पर्याप्त नहीं हैं, खासकर जिले के दूरदराज के ग्रामीण इलाकों में। सरकार को ग्रामीण लोगों के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देने के लिए बहुत सावधान रहना चाहिए। जिले में सभी प्राथमिक स्तर के छात्रों, इंटरमीडिएट स्तर पर सभी लड़कियों और विश्वविद्यालय स्तर पर सभी अनुसूचित जाति के छात्रों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जा रही है।

तीव्र जनसंख्या वृद्धि देश की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्था को प्रभावित करती है। जनसंख्या नीति, जनसंख्या वृद्धि को कम करने के लिए एक सुविचारित कदम है। स्वास्थ्य पूर्ण शारीरिक, मानसिक या सामाजिक कल्याण की स्थिति है, न कि केवल रोग या दुर्बलता का अभाव। इसलिए, परिवार कल्याण कार्यक्रम अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने और परिवार में तनाव कम करने में अत्यंत आवश्यक सिद्ध हुआ है। स्वास्थ्य सभी के लिए अच्छा है। मानव जाति के हित में, सभी के लिए स्वास्थ्य और सभी के लिए स्वास्थ्य होना आवश्यक है। इसलिए, सरकार की गहन, निवारक और प्रोत्साहनकारी योजनाओं के माध्यम से लोगों के स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार करना अत्यंत आवश्यक है।

संदर्भ

1. तिवारी, अभय. उत्तर प्रदेश में जनसंख्या और विकास: जनगणना के आंकड़ों का उपयोग करते हुए जिला स्तरीय विश्लेषण. इंटरनेशनल जर्नल ऑफ हेल्थ. 2015;3:60. 10.14419/ijh.v3i2.5479.
2. कपूर पूजा. भारतीय महिला सशक्तिकरण में डॉ. बी. आर. अंबेडकर के योगदान पर एक विश्लेषणात्मक अध्ययन. 2021;20:3347-3353. 10.17051/ilkonline.2021.01.378.
3. कुमार कन्हैया. स्वास्थ्य संसाधनों तक पहुँच में अंतर: उत्तर प्रदेश, भारत में दलित उप-जातियों के बीच असमानताओं का विश्लेषण। जाति / सामाजिक बहिष्कार पर एक वैश्विक पत्रिका। 2022;3:405-420. 10.26812/caste.v3i2.449.
4. धवलेश्वर, चिदानंद, बनसोडे, चंद्रशेखर. डॉ. बी.आर. अंबेडकर हाशिए पर पड़े वर्गों के लिए एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में। इंटरनेशनल रिसर्च जर्नल ऑफ ह्यूमन रिसोर्सिज एंड सोशल साइंसेज। 2017;4:344-350. 10.2139/ssrn.3044336।
5. पंकज, अजीत, अहमद मोहम्मद, आलम इफ्तिखार. डॉ. अंबेडकर के मानवाधिकारों के विचार और समाज कार्य शिक्षा में उनके शिक्षण का दायरा: पाठ से संदर्भ तक। समाज कार्य शिक्षा। 2024, 1-13. 10.1080/02615479.2024.2386312।

6. होक, एम.डी. अरेफुल. भारत के पश्चिम बंगाल के मालदा जिले में मैनुअल स्कैवेंजर्स श्रमिकों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति, स्वास्थ्य स्थिति और प्रमुख समस्याएँ, एक केस स्टडी. 2024;6:301-312.
7. दारजी दिलीप. डॉ. भीमराव रामजी अंबेडकर: जातिगत अन्याय के विरुद्ध उनके संघर्ष और सामाजिक एवं संवैधानिक सुधार में उनकी विरासत की समीक्षा. 2025;8:105-117. 10.2018/SS/202504017.
8. गाडेकर दीपक. भारत में जनसंख्या वृद्धि और समस्याएँ: एक भौगोलिक अध्ययन। 2024. 10.5281/जेनोडो.14355041.
9. अंकित सिंह, रुचिका सिंह. जनसंख्या वृद्धि और उसके वितरण का स्थानिक विश्लेषण: पूर्वी उत्तर प्रदेश का एक केस स्टडी।, 2020.
10. कैटरिन ग्रॉसमैन, एलेना टुबिना. शहरी भूगोल में गरिमा: एक बातचीत की शुरुआत। मानव भूगोल में संवाद। 2022, 12. 204382062210756. 10.1177/20438206221075697।
11. बंसोडे संभाजी. मालशिरस तहसील में जनसंख्या घनत्व: एक भौगोलिक विश्लेषण. शिक्षा में अनुसंधान की समीक्षा. 2016;6:4.
12. महाश्वेता चक्रवर्ती, आदित्य सिंह. भारत में युवा महिलाओं के बीच पर्याप्त मासिक धर्म स्वास्थ्य और स्वच्छता संसाधनों तक पहुँच का भौगोलिक विश्लेषण। वैश्विक सामाजिक कल्याण। 2024, 1-12. 10.1007/s40609-024-00359-1।
13. चिन यी, ली. जनसंख्या घनत्व और गतिशीलता पर एक व्यवस्थित साहित्य समीक्षा. एशियन जर्नल ऑफ रिसर्च इन एजुकेशन एंड सोशल साइंसेज. 2024;6:327-337. 10.55057/ajress.2024.6.1.30.
14. योरफी केनेडी. बर्मिंघम में जनसंख्या घनत्व और भूमि क्षेत्र गतिशीलता का तुलनात्मक विश्लेषण।, 2024.
15. अन्ना प्लुश्टेवा. सार्वजनिक भूगोल में गरिमापूर्ण बातचीत: महामारी के समय में सार्वजनिक सहभागिता की नैतिकता. क्षेत्र. 2022, 55. 10.1111/क्षेत्र.12818.
16. सारा सफ्रांस्की. गरिमा की स्थानिक राजनीति के लिए। मानव भूगोल में संवाद। 2022, 12. 204382062211336. 10.1177/20438206221133616।

Creative Commons (CC) License

This article is an open access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY 4.0) license. This license permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original author and source are credited.